

**Dr. P. S. Deshmukh:** There is no proposal at present for associating any foreign experts.

**Shri D. C. Sharma:** May I know if this Commission will be empowered to visit other countries also where forestry has attained a high degree of perfection?

**Dr. P. S. Deshmukh:** It is not one of the functions of this Commission to study forestry; we have already sufficient knowledge, but occasion may arise probably if they consider it necessary to undertake such a study.

**The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain):** I may add that the question of setting up the Commission is under consideration and the hon. Member will do well to wait for a short while until things have crystallised.

#### L. L.O. Committee on Plantation

\*501. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of Labour be pleased to state:

(a) the main decisions arrived at the third session of International Labour Organisation Committee on Plantation which was held at Geneva from the 17th to the 29th October, 1955; and

(b) how far Indian plantation labourers will be benefited from those decisions?

**The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali):** (a) and (b). These have not been communicated yet but will be examined on receipt.

I may, however, add that the report since received from our delegate shows that he has succeeded in persuading the governing body to place the subject of plantation labour on the agenda of the International Labour Conference so that a convention or recommendation may be adopted by the Conference on this subject at an early session of the International Labour Conference. The Government of India has been desiring this for some time past.

**श्री विभूति मिश्र :** कमेटी के जो फैसले होते हैं उनको प्लांटेशंस पर लागू करने के लिये क्या भारत सरकार कानूनी कार्रवाई भी करती है ?

**मम मंत्री (श्री खंडूभाई वेसाई) :** सरकार, कानूनी कार्रवाई लेती है ।

**श्री विभूति मिश्र :** ये जानना पड़ता कि चाय के और काफी के जो बायान हैं,

उन में जो मजदूर काम करते हैं और जिनके पास घरबार की सुविधायें नहीं हैं और मजदूरी भी कम मिलती है, उनको इस कमेटी के फैसले के अनुसार सरकार क्या सहूलियतें देगी ?

**श्री प्राविश प्रली :** इसके बारे में प्लांटेशन लेबर एक्ट १९५१ में पास हुआ था और उसकी बहुत सी प्राविजस को प्रमल में लाया गया है ।

#### Renewals of Railway Line Sleepers

\*504. **Shri M. S. Gurupadaswamy:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total mileage of sleeper renewals completed during the current year till the 30th September, 1955 ;

(b) whether it is a fact that the progress of work is not according to the schedule ;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken for early execution of this work ?

**The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) About 408 miles.

(b) Yes, Sir.

(c) Non-availability of sleepers and/or fittings in time.

(d) All possible arrangements are being made to procure sleepers and fitting from indigenous sources and abroad to meet requirements.

**Shri M. S. Gurupadaswamy:** May I know the total mileage of railways on which renewals have still to take place?

**Shri Shahnawaz Khan :** Every year we have a programme for these renewal and generally we programme about 1,000 miles every year and most of the work is done after the monsoon.

**Shri M. S. Gurupadaswamy:** May I ask whether it is a fact that in the Southern Railway the renewals are done very slowly as compared to the renewals in the other Railways, and may I know the reasons for it?

**Shri Shahnawaz Khan :** In most cases the causes are beyond our control for one thing, the availability of wooden sleepers. There is an acute shortage of wooden sleepers. Also, orders for metal

sleepers or cast iron sleepers, which are imported, are placed by Ministries other than the Railway Ministry. We have to depend upon the availability of these materials.

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि एक तरफ तो स्लीपर्स की बहुत ज्यादा कमी है और दूसरी तरफ हर साल कई लाख स्लीपर काश्मीर के पास भे जाते हैं, यदि हाँ तो इसको रोकने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** मुम्किन है कि स्लीपर्स की इतनी कमी न हो जितनी कि आनरेबल मੈम्बर ने बतलाई है लेकिन जो हमारी कठिनाई है वह यह है कि जो दाम स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, मुकर्रर करती है, वह उन रेट्स से जो हम तय करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम ब्राड गेज के एक स्लीपर के १८ रुपये तय करते हैं तो मांग होती है कि २१ रुपये, २२ रुपये और २३ रुपये तक स्लीपर के दाम हों। हमने दामों को बढ़ाना भी चाहा है लेकिन तब भी हमें इस के बारे में पूरी सफलता नहीं मिली है। इस बास्ते लकड़ी के स्लीपर रहते हुए भी जहाँ तक कीमत की बात है, स्टेट गवर्नमेंट मदद करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** मेटल स्लीपर और वुडन स्लीपर के दाम में कितना फर्क है और मेटल स्लीपर वुडन स्लीपर के मकाबले में कितनी ज्यादा बेर चलते हैं ?

**The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan) :** I think the wooden sleepers' age is about 15 to 18 years, whereas the age of cast iron or steel sleepers is about 30 years; they are costlier to begin with, but in the long run they are cheaper.

## कोलम्बो योजना

**\*५०५: श्री भागवत झा आजाद :** क्या रेलवे मंत्री १६-६-५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८८३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन अब तक आस्ट्रेलिया से कल कितने रेल के डिब्बे प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) माल की पहली खेप किस तारीख को आई थी ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासद्विध (श्री शाहनवाज खाँ) :** (क) कोई नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**श्री भागवत झा आजाद :** मैं जानना चाहता हूँ कि देश की आवश्यकता के अनुसार जब कि देश में ही कोचिज नहीं बन रही है, तो क्या यह सवाल सरकार के विचाराधीन है कि विदेशों से भी डिब्बों का आयात किया जाए, यदि हाँ, तो किन किन देशों से मंगाने का विचार किया जा रहा है ?

**श्री शाहनवाज खाँ :** यह जो सवाल है यह तो सिर्फ कोलम्बो योजना के बारे में है। मेरा खयाल है जो सवाल अब आनरेबल मੈम्बर ने किया है वह इस सवाल से जरा बाहर मालूम होता है।

**श्री भागवत झा आजाद :** कोलम्बो योजना के ही अन्तर्गत क्या सरकार आस्ट्रेलिया के अलावा किसी दूसरे देश से भी डिब्बों के आयात करने का विचार कर रही है ?

**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** आम तौर पर हमारा विचार यही है कि हम सवारी डिब्बे बाहर से न मंगायें लेकिन कोलम्बो योजना के मातहत हमें सस्ते दामों पर वह चीजें मिलती हैं रेलवेज को चाहे न मिलती हों अगर गवर्नमेंट प्राफ इंडिया को मिलती हैं। इस वजह से